

35 हजार एकड़ में बस रहा बीडा बदलेगा बुंदेलखंड की किस्मत

पांच हजार से अधिक लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार, पर्यटन उद्योग भी बढ़ेगा



अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। 35 हजार एकड़ में बस रहे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की मदद से पूरे बुंदेलखंड की आर्थिक परिस्थिति में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। बीडा में कई जानी-मानी कंपनियों को जगह मिलेगी। इससे पांच हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार समेत आय के दूसरे रास्ते खुलेंगे। बीडा अफसरों का कहना है कि मास्टर प्लान को मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। अगले साल से कंपनियों की बसावट भी शुरू होगी।

बीडा को बुंदेलखंड खास तौर से

1500 करोड़ रुपये से आरंभ होंगे विकास कार्य
बीडा में विकास कार्य 400 हेक्टेयर से आरंभ होंगे। आंतरिक सड़कें समेत बिजली एवं अन्य औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए सुविधा जुटाने में करीब 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे बीडा बोर्ड से मंजूरी भी दी जा चुकी है।

उद्योगों के लिए 35 फीसदी जमीन प्रस्तावित

बीडा के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान में सर्वाधिक 35 फीसदी जमीन उद्योगों के लिए तय की गई है। इसके साथ, आवासीय इकाइयों के लिए 16.2, व्यावसायिक 3.2, प्रतिष्ठान 2.8, मिश्रित भू उपयोग 7.9, ग्रीन बेल्ट 15.1, परिवहन के लिए 15.1 प्रतिशत जमीन सुरक्षित रखी जाएगी। इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आपत्तियों की सुनवाई हो चुकी है। अब शासन से मंजूरी का इंतजार है।

झांसी में लोग बेहद उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क, आईटी हब समेत अलग-अलग उद्योगों के लिए कंपनियों को जगह दी जानी है। यहां मेगा फूड पार्क भी बनेगा। बीडा अफसरों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के लिए अमेरिका, जापान एवं कोरिया के शहर मॉडल

बनाए गए हैं। इनकी तर्ज पर यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया होंगी। इन सबके चलते न सिर्फ रोजगार की मांग बढ़ेगी बल्कि पर्यटन, होटल उद्योग को पंख लगेगा। स्थानीय लोगों की इसमें हिस्सेदारी रहेगी।

आर्थिक विशेषज्ञ डा. अनुपम वशिष्ठ का कहना है कि बीडा से

फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ेगा

बीडा को रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ने की कवायद हो रही है। फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ने पर इसे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जा सकता है। यह कॉरिडोर दादरी से मुंबई के जवाहर लाल नेहरू पोर्ट तक जाता है। इसके जरिये माल दुलाई में आसानी होगी।

पूरे बुंदेलखंड में आर्थिक बदलाव की उम्मीद है। रोजगार के लिए बाहर जाने वालों को यहां रोजगार मिल सकेगा। वहीं, सीईओ अमृत त्रिपाठी का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कार्य तेजी से चल रहा है। मास्टर प्लान भी मंजूरी के लिए भेज दिया गया। कंपनियों की बसावट भी जल्द आरंभ होगी।